

Title: Need to release the funds sanctioned as subsidy towards construction of dwelling units for Beedi workers in Uttar Pradesh.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : महोदय, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं० एम.११०१५/१९/०६ डब्ल्यू. १११, दिनांक १९ फरवरी, २००७ द्वारा उ०प्र० के जनपद इलाहाबाद के ७९ एवं कौशाम्बी के २० वाराणसी में ०५ बीड़ी श्रमिकों के आवास निर्माण हेतु आर.आई.एच.एस. २००५ के अंतर्गत धनराशि रु० २०८० लाख की सब्सिडी स्वीकृत की गई। आदेश में उल्लेख किया गया है कि सब्सिडी की धनराशि श्रमायुक्त कार्यालय कानपुर को उपलब्ध कराई जाये। इस संबंध में अपर श्रमायुक्त कानपुर ने १५ जून, २००७ को प्रदेश सरकार को लिखा परन्तु धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई। पत्र सं० ९०२/०५/प्र.बी.सी. ३२/०७ दूसरा रिमाइन्डर श्रमायुक्त कानपुर द्वारा फिर प्रदेश सरकार को २७.७.०७ को दिया गया। जिसकी पत्र सं० १२१२-१३ है। इन बीड़ी श्रमिकों ने पांच पांच हजार का बैंक ड्राफ्ट कर्ज लेकर दिया है। जिसका ब्याज बढ़ रहा है। श्रमिकों में भारी रोÂा व्याप्त है। मेरा भारत सरकार श्रम मंत्रालय से अनुरोध है कि स्वीकृत धनराशि २०८० लाख को अवमुक्त कराकर श्रमायुक्त कानपुर को भिजवाने का कÂट करें। जिससे श्रमिकों को अनुदान की राशि मिल सके।